भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 29
18.07.2016 को उत्तर के लिए

जलवायु पर 'हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव आरोरल रिसर्च प्रोग्राम' (हार्प) का प्रभाव

29. श्री सुखेन्दु शेखर राय:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अमेरिकी वायु सेना और नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 'हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव आरोरल रिसर्च प्रोग्राम' (हार्प) की जानकारी है, जो भारत सहित विश्व की जलवायु पर घातक प्रभाव डाल सकता है और इसके परिणामस्वरूप कृषि और पारिस्थितिकी प्रणालियां अस्थिर हो सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए निवारक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री अनिल माधव दवे)

(क) उपलब्ध वैज्ञानिक साहित्य के अनुसार अमेरिका ने हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव आरोरल रिसर्च प्रोग्राम (हार्प) नामक एक प्रकार का हथियार विकसित किया है। हार्प केन्द्रित तथा संचालन योग्य इलैक्ट्रोमैग्नेटिक बीम से ऊपरी वायु मंडल पर प्रहार करता है। हार्प सूपर-पावरफुल आयनोस्फेरिक हीटर का एक उन्नत मॉडल है जिसके कारण विश्व में उष्णता आ सकती है और ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव हो सकता है। दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन, मानवजनित उत्सर्जनों के कारण होने वाली घटना है।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन में प्रमुख फसलों अर्थात गेहूं, मक्का, सरसों, आलू और ज्वार के पैदावार में कमी की दृष्टि से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का अनुमान लगाया गया है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के खतरे को पहचानते हुए, सरकार ने

जलवायु परिवर्तन तथा इससे संबंधित मुद्दों का निराकरण करने के लिए जून, 2008 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) शुरू की है। एनएपीसीसी में सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, पर्यावास, जल, हिमालयी पारिप्रणालियों की सततता, वानिकी, कृषि और जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशन शामिल हैं जिनसे ग्रीन हाऊस गैसों के उपशमन और पर्यावरण, वनों, पर्यावास, जल संसाधनों तथा कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन से संबंधित मुद्दों का निराकरण होता है। एनएपीसीसी का कार्यान्वयन विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भी एनएपीसीसी के उद्देश्यों के अनुरूप राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार करने तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को रेखांकित करने का अनुरोध किया गया है। अब तक 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी एसएपीसीसी तैयार कर ली हैं।

*****